RE. HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON REVISION OF WAGES

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you just yield for a minute? I want to inform our Member, Mr. Ramdas Agarwal, that he has got a Half-an-Hour listed at 6.00 p.m. As our work is going a little slow, I have at least another 10 to 12 people to seek clarifications on this. So, would you still like to press for the Half-an-Hour later on or shall we decide that we do not have it today? I am saying so because it will take a long time. आपने कहा था कि आपको कहीं जाना है। तो मैं आपकी इत्तिला के लिए कह रही हूं कि इसमें समय लगेगा। 12–15 लोग और हैं और इसमें पूछने वाले हैं। तो आपको समय लगेगा। इसलिए आपका हाफ एन आवर अगर आप इजाजत दें और न लें आज, अगले सेशन में ले लें? अगर आपको तकलीफ न हो।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): 7 बजे तक भी अगर आप कर लेंगी तो ठीक है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): अगले सेशन के लिए विचार हो।

श्री रामदास अग्रवाल: मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि विषय बहुत वर्ष से चलता जा रहा है और सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा टालमटोल की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति अपना रही है जिसके कारण आवश्यक है कि इस विषय को लिया जाए। अगर आप उचित समझें तो 7 बजे भी समय हो तो मेरे लिए रुकना उचित होगा।

उपसभापति: यह मामला आज चूंकि शुरू हो चुका है, एल०टी०टी०ई० का मामला हमारे सदस्य कई दफा इस मामले को उठा चुके थे इसलिए होम मिनिस्टर ने यह बात कही। अगर आप कहें आप 7 बजे तक बैठना चाहें तो ठीक है लेकिन यह कम्प्लीट हो जाए। इसके बाद स्पेशल मेंशन भी है। मेरे पास 18 स्पेशल मेंशन हैं।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Today is the last day and special mentions have been held over for days together. I have to catch a flight. So, I ould make a request to the Deputy Chairman to take up special mentions soon after this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We cleared 36 special mentions yesterday. (*Interruptions*). Okay, we will take up special mentions after this.

SHRI ASHIS SEN: I have to catch a flight.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us finish these clasifications and then you can catch your flight.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि आधे घटे की चर्चा के विषय में मैंने आपसे जो आग्रह चाही व वछावत आयोग के बारे में है। पत्रकारों के वेतन के संबंध का विषय है। बहुत गंभीर विषय है। कई वर्षों से रहा है। लेकिन इसमें सरकार ने जो भी कुछ करने का प्रयत्न किया है उस से ऐसा अनुभव होता है कि उन्होंने ठीक प्रकार से इसमें कार्यवाही करने में संकोच जाहिर किया। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम सरकार अगले सत्र तक इंतजार न करे कि इस मामले पर डिसकशन हो और फिर वे कदम उठायें। मैं उनको पत्र के द्वारा भी यह जानकारी दे दूंगा कि उनको किन किन बातों पर कदम उठाना चाहिए जिससे पत्रकारों को कम से कम राहत का अनुभव तो हो और उनको जो कानून सम्मत मिलना हो वह तो मिले। इतना प्रयत्न तो सरकार करे। इतना आश्वासन दे दें। अगले सत्र के लिए आप उसको रख सकती हैं इसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

उपसभापति: मंत्री जी आप कुछ आश्वासन तो दीजिए। हमारे मेम्बर इतना कोआपरेट कर रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): This issue is very much alive in the mind of the Government. In fact, on 30th of April there was a Starred Question and the House spent 35 minutes on questions and answers. I gave a lot of assurances, including that the pension schemes for the working journalists were at a final stage. I had given a promise in this House that I would call a meeting of the Association of Journalists. This meeting has been fixed for 29th of this month. All other issues are being looked into. I can assure that by the next Monsoon Session of the House you will have a better opportunity to discuss all these things because on the pension scheme a Bill will be brought here. (*Interruptions*).

श्री रामदास अग्रवाल : वेतन बोर्ड को गठित करवाने की कृपा करें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Maybe, next session, he may not have a bigger or better opportunity to discuss but to thank you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : दूसरा वेतन आयोग बिठा कर उसको खत्म कर दें । पालेकर अवार्ड को छोड़ कर आप लागू कर दें । बात खत्म हो गई । . . . (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह : उसके लिए टाईम निर्धारित कर दीजिए । . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : उन्होंने कर दिया ना : . . . (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह : आप सुनिये । आप क्यों दोहरा रही हैं । . . . (**व्यवधान**) चेयर का यह काम है आपका काम नहीं है । . . . (**व्यवधान**)

Mrs. Margaret Alva, you are not the Deputy Chairman or Chairman. Why are you shouting from there? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI MATI MARGARET ALVA): We can't follow you. . . (*Interruptions*) . . .

उपसभापति : शंकर दयाल जी, आप गुस्सा नहीं करिए ।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Why are you dictating?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I said, there is shouting from there and we cannot hear you . . . (*Interruptions*) . .

उपसभापति : नहीं, नहीं, प्लीज कर दयाल जी, गुस्सा मत करिए ।

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, मैं सिर्फ एक और बात का आग्रह मंत्री जी से करना चाहता हूं । . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : शंकर दयाल जी, जितना आपका गुस्सा है शाऊट है आप मेरे ऊपर डाल कर इधर कर दीजिए : उनको जो कहना है वह मेरे ऊपर डाल दें । मैं आप तक पहुंचा दूंगी ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम उन्होंने डाइरैक्ट मेरे ऊपर डाला ।

उपसभापति : आज आखिरी दिन है । गुस्सा नहीं करिए : मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया । बहुत कम लोग देते है । हो गया, । 29 तारीख को बात करेंगे । Let me act as a shock-absorber. Please.

श्री रामदास अग्रवाल : कृपया मुझे एक मिनट दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no, डिसकशन नहीं होगा । It will be over. That is his right.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, there are four issues. One: Implementation of the Bachawat Award. I have mentioned in this House that we have written to the State Governments to form tripartite

committees and to monitor them, but we have not received the replies from the Governments. This is what I have said.

उपसभापति : अभी बीच में आप सवालात मत कीजिए व न.--

I will make you wait till 7'o clock.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, today I am happy to inform you that eight major States have constituted tripartite committees and they are constantly monitoring them now. This is one issue. The second issue is constitution of another Wage Board. I said that this matter is lying with the Supreme Court on the criteria to be determined. Basic issues are being challenged. As soon as the matter is settled by the Supreme Court, Government will think about constituting a new Wage Board. That is the second one. The third one is about the health, hygiene and safety of the working journalists. An expert committee has been constituted for that. They have given a report. The report is referred to an empowered committee. I am told the empowered committee will submit its report by July. This is the third one. The fourth one is the pension scheme. I said, it is at the final stage, and I am taking a final round of meeting with the journalists on the 29th. Beyond that, Madam, I cannot say anything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Never in the history of Rajya Sabha was a Half-an Hour discussion over in six to seven minutes. That is very good.

श्री रामदास अग्रवाल : मैं केवल एक बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं । यह बहुत आवश्यक विषय है ।

SHRI KAPIL VERMA: Whether he is accepting...(*Interruptions*)... We want the scheme according to this. Kindly give this assurance...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, have you suspended the question?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I have to continue with Mr. Sukomal Sen.

श्री रामदास अग्रवाल : पी०टी० आई० एन०आई०में जो वेतनमान दिये जा हैं अंग्रेजी संवाददाताओं को जो अंग्रेजी में काम करते हैं उन कर्मचारियों का और यूनीवार्ता में जो कर्मचारी हिंदी में काम करते हैं उनको वह समान वेतन नहीं दे । बचावत आयोग के अन्तर्गत वेतन में . . . (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ramdasji, now don't take advantage of the leniency of the Chair....(*Interruptions*)...

श्री रामदास अग्रवाल : . . . ऐसा भेदभाव हिंदी और अंग्रेजी में काम करने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहिए । यह हिंदी का अपमान होगा, यदि हिंदी में काम करने वाला कर्मचारी कम वेतन प्राप्त करता है . . . (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : हिंदी में काम करने वाले लोगों को भी अंग्रेजी में काम करने वाले के बराबर तनख्वाह मिले इसकी जरूर व्यवस्था करें ।

श्री रामदास अग्रवाल : यह बिलकुल अनुचित है ।

उपसभापति : आप ध्यान रखिये कि किसी किस्म का भेदभाव न हो । There should be no discrimination on the basis of language. And while you have the meeting on the 29th, take care of that. Now, that is over.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही नहीं रहे, भारतीय भाषाओं का इसमें कर दिया जाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said it, that there should be no discrimination on the basis of any language. Okay. We also have listed, discussion on the Petroleum Ministry. I don't think we can have discussion on that now. If the Members want to sit the whole night, they are welcome; we can discuss it till 12 midnight.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMI (Uttar Pradesh): Guillotine the Minister —I am sorry—the Ministry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In the next session we can have it. By that time the Minister will have some better situation in the country, we hope, and we wish that the Petroleum Ministry will have some good news for us also. So, we can release him... (*Interruptions*). If the House agrees, then, I will ask the Minister.

श्री रामदास अग्रवाल : मैडम, अगले सैशन के लिए... (व्यवधान) अगले सत्र के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए।

उपसभापति : मंत्री जी, आपके मंत्रालय के विषय में जो यहां चर्चा होने का लिस्ट किया था, वह समय नहीं होने के कारण हाउस ने यह तय किया है कि वह नहीं होगा और उम्मीद करते हैं कि आते सेशन में आप कुछ अच्छे माहौल में जब डिसकस करेंगे तो अच्छा रहेगा।

अब अगर आप बैठना चाहें तो बैठिए, सुनिए डिसकशन।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Your remark suggested that you were going to guillotine the Minister instead of the Ministry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I never say such things ever. Not even you I want to guillotine, though you try to guillotine the time of the House most of the time.

STATEMENT RE. DECLARATION OF L.T.T.E. AS UNLAWFUL ASSOCIATION —Contd.

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, I was telling that the step taken by the Government of banning the organisation, was necessary. This is not a complete step.

Demands have been raised just now by my friends. Shri Subramaniam Swamy has also raised the demand. Some news is going round about Government's attempt to seek extradition of the LTTE leader, Prabhakaran. My friend advised a method that if they don't do it, then, we should adopt the method adopted by the U.S. Government against Libya. I do not support that foolish method of the U.S. Government: rather I would oppose it: But I would like to know the reaction of the Government on this demand, whether the Government is really seeking his extradition and if so what the reaction of the Sri Lankan Government is.

Madam, another problem is about the LTTE's links with other separatist and terrorist groups in India. After banning them, what steps will the Government take to snap those links between the LTTE and the terrorist and separatist groups in India and to stop the flow of arms to them from the LTTE?

Also, about local recruits being taken by the LTTE to Jaffna and sending them back to Tamil Nadu, what steps has the Government taken to apprehend the LTTE cadres in India and to stop the recruitment of local Tamil youth and sending them to Jaffna for training and again sending them back to India? What steps are being taken by the Government to stop it?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Bihar): Madam, a point of order. A meeting is also going on there. Kindly check if first. No, no, no, this is not the way.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The CBI Minister cannot hold a meeting there. (*Interruptions*)